

भारत में ग्रामीण शिक्षा- एक सिंहावलोकन

मीना *

कल्पना पारीक**

भारत गाँवों का देश है। देश की करीब 70 फ़ीसदी से ज़्यादा आबादी गाँवों में रहती है। हालाँकि यह भाग धीरे धीरे कम होता जा रहा है जिसका मुख्य कारण ग्रामीणों का गाँव से शहरों की ओर पलायन भी है। पलायन का मुख्य कारण है शहरों में गाँवों की अपेक्षा बेहतर शिक्षा सुविधाएँ एवं रोज़गार के अवसर। किसी भी समाज का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब उस समाज के बीच साक्षरता दर में बढ़ोतरी दर्ज़ हो। जब समाज साक्षर होगा तो देश भी साक्षर होगा। केंद्र सरकार की ओर से ग्रामीण साक्षरता दर बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। विभिन्न योजनाओं की बदौलत ग्रामीण साक्षरता दर में बढ़ोतरी भी दर्ज़ हुई है। वर्ष 2001 की अपेक्षा 2011 के साक्षरता दर के आँकड़े इस बात का सबूत दे रहे हैं कि ग्रामीण भारत शिक्षा के मामले में बदल रहा है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी भारत की कुल जनसंख्या का 68.84 प्रतिशत निवास करता है इसलिए इस क्षेत्र में शिक्षा की उपयोगिता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। शिक्षा न केवल लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराने में सहायता करती है बल्कि लोगों में नयी सोच एवं दिशा प्रदान करने में भी सराहनीय योगदान दे रही है, जिससे ग्रामीण परिवारों का जीवन स्तर पहले की अपेक्षा बेहतर हुआ है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में सबके लिए शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि गाँवों की खुशहाली में ही भारत की खुशहाली और प्रगति निहित है।

* शोधार्थी (यू.जी.सी.-एस.आर.एफ.) शिक्षा विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर।

** सहायक प्रोफ़ेसर, श्रीस्वरूपगोविन्दपारीक स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, जयपुर।

‘सा विद्या या विमुक्तये’ अर्थात् शिक्षा वहीं जो मुक्त करती है मुक्ति का अर्थ तमाम बंधनों, अंधविश्वासों एवं कुरीतियों से मुक्ति पाना और नयी समझ के साथ नयी दृष्टि का निर्माण करने से है। विश्व के लगभग सभी समाजों और कालों में शिक्षा का महत्व एक समान बना रहा है। वैदिक काल में शिक्षा को वह प्रकाश माना गया जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रकाशित करने का सामर्थ्य रखता है। शिक्षा के महत्व पर एक चीनी कहावत है कि ‘किसी राष्ट्र को एक वर्षीय योजना बनानी हो तो कृषि को, दस वर्षीय योजना बनानी हो तो वन को, सौ वर्षीय योजना बनानी हो तो शिक्षा को प्राथमिकता दें।’ शिक्षा की आवश्यकता को समझकर ही स्वतंत्र भारत के शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1940 में एक शिक्षक सम्मेलन में कहा था ‘बुनियादी शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है क्योंकि उसके बगैर वह बतौर नागरिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी नहीं निभा सकता है।’ विवेकानंद ने कहा है-

‘राष्ट्रीय शिक्षा की अवहेलना पाप है। साक्षरता से ही महिलाओं और कमज़ोर वर्गों को समर्थ बनाया जा सकता है।’ अतः यह एक सर्वविदित सत्य है कि शिक्षा किसी भी व्यक्ति समाज और राष्ट्र के विकास की धुरी होती है। शिक्षा का संबंध सिर्फ साक्षरता से ही नहीं है बल्कि शिक्षा चेतना और उत्तरदायित्व की भावना को जाग्रत करने वाला औज़ार भी है। शिक्षा को एक मापक या पैमाने के तौर पर देखा जाता है। जिसके आधार पर व्यक्ति, राज्य या देश का मूल्यांकन किया जाता है और यदि इस मूल्यांकन के दृष्टिकोण से हम भारत में साक्षरता की स्थिति को देखें तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल साक्षरता स्तर 74.40 प्रतिशत है जोकि वर्ष 1951 में मात्र 18.33 प्रतिशत थी।

भारत की कुल जनसंख्या 121.02 करोड़ है। इसमें से 83.31 करोड़ जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से हमारे गाँव बहुत पिछड़ी हुई दशा में हैं। वहाँ के रहने वालों

तालिका 1

भारत में साक्षरता वृद्धि दर (1951-2011)

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1951	18.33	27.16	8.86
1961	28.30	40.40	15.35
1971	34.45	45.96	21.97
1981	43.57	56.38	29.76
1991	52.21	64.13	39.29
2001	65.38	75.85	54.16
2011	74.40	82.14	65.46

(स्रोत - भारत की जनगणना 2011)

तालिका 2

साक्षरता दर (प्रतिशत में)

वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	महिला
1951 (5 + आयु वाले)			
ग्रामीण	12.10	19.02	4.87
शहरी	34.59	45.60	22.33
कुल	18.33	27.16	8.86
1961 (5 + आयु वाले)			
ग्रामीण	22.50	34.30	10.10
शहरी	54.40	66.00	40.50
कुल	28.30	40.40	15.35
1971 (5 + आयु वाले)			
ग्रामीण	27.90	48.60	15.50
शहरी	60.20	69.80	48.80
कुल	34.45	45.96	21.97
1981 (5 + आयु वाले)			
ग्रामीण	36.00	49.60	21.70
शहरी	67.20	76.70	56.30
कुल	43.57	56.38	29.76
1991 (5 + आयु वाले)			
ग्रामीण	44.70	57.90	30.60
शहरी	73.10	81.10	64.00
कुल	52.21	64.13	39.29
2001(5 + आयु वाले)			
ग्रामीण	59.40	71.40	46.70
शहरी	80.30	86.70	73.20
कुल	65.38	75.85	54.16
2011 (5 + आयु वाले)			
ग्रामीण	68.95	78.57	58.75
शहरी	84.98	89.67	79.92
कुल	74.40	82.14	65.46

को प्रायः अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। न वहाँ रोजगार के स्थायी अवसर लोगों को भली प्रकार मिल पाते हैं, और न ही शिक्षा, चिकित्सा तथा मनोरंजन आदि की सुविधाओं का समुचित प्रबंध है। साथ ही वहाँ भूमि, जाति-पाति आदि के सिलसिले में झगड़े उठते रहते हैं। इसके विपरीत शहरी जीवन के अपने अनेक आकर्षण हैं। साधारण तौर से शहरों में शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा, मनोरंजन आदि की सुविधाएँ अपेक्षाकृत अधिक मिलती हैं और रोजगार पाने की संभावनाएँ भी अधिक होती हैं। फलस्वरूप प्रतिवर्ष बहुत से लोग गाँव छोड़कर शहरों में आकर बस जाते हैं।

जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कुल साक्षरता 68.95 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्रों में 84.98 प्रतिशत है। गाँवों में पुरुषों एवं महिलाओं की साक्षरता क्रमशः 78.57 एवं 58.75 प्रतिशत है। गाँवों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की साक्षरता स्तर में तेज़ी से वृद्धि हुई है। ग्रामीण व शहरी साक्षरता के तुलनात्मक स्वरूप को तालिका 2 के द्वारा दर्शाया गया है।

हालाँकि विगत वर्षों में ग्रामीणों की साक्षरता स्थिति में लगातार सुधार हुआ है और वह सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ही नतीजा है फिर भी गाँवों में आज भी 31 प्रतिशत जनसंख्या अशिक्षित है। राजस्थान और उत्तरप्रदेश के विद्यालय में नहीं पढ़ रहीं 11-14 वर्ष की बालिकाओं का अनुपात 2011 में क्रमशः 8.9 प्रतिशत और 9.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2012 में 11 प्रतिशत से अधिक हो गया जो कि चिंतनीय विषय है।

शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार के तमाम आँकड़ों के बावजूद आज भी भारत की साक्षरता दर तीसरी दुनिया के देशों की तुलना में बहुत कम है। इसका प्रमुखकारण भारत के शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों का अन्य देशों की तुलना में कम प्रभावशाली होना है। अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के चलते भी भारत के शैक्षिक कार्यक्रम उतने सफल नहीं हो पाते और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे, खासतौर से बालिकाएँ। ग्रामीण बालिकाओं के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में अनेक सांस्कृतिक और परंपरावादी बाधाएँ हैं जो उन्हें आगे पढ़ने-बढ़ने से रोकती हैं।

भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या लगभग 15.3 करोड़ है। इसमें से लगभग 80 प्रतिशत बच्चों का स्कूलों में नामांकन हुआ है और इनमें से लगभग 50 प्रतिशत पहली कक्षा के बाद पाँचवी कक्षा तक पहुँचने से पहले ही बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। प्राथमिक स्कूल तक की शिक्षा (पाँचवी कक्षा तक) प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या भारत में 38 प्रतिशत है जबकि चीन में 70 प्रतिशत, मिश्र में 64.3 प्रतिशत, मलेशिया में 97.2 प्रतिशत, श्रीलंका में 90.8 प्रतिशत और सिंगापुर में 90 प्रतिशत है। भारत में बालिका शिक्षा की स्थिति अत्यंत दयनीय है। एक स्वयंसेवी संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में नामांकित कुल 100 बालिका छात्राओं में से पाँचवी कक्षा तक पहुँचते पहुँचते उनकी संख्या 40 रह जाती है और आठवीं कक्षा तक 18 दसवीं कक्षा तक 10 और बारहवीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते उनकी संख्या

मात्र 1 रह जाती है। यह स्थिति बीमारू राज्यों (बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान) में 30 प्रतिशत से भी कम है। भारत के अन्य राज्यों में भी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की अपेक्षा और भी कम रहती है।

इस प्रकार की परिस्थितियाँ निश्चित ही हमारे पूर्ण साक्षर विकसित भारत बनने के सपने को धुमिल कर सकती हैं। अतः उक्त परिस्थितियों को जन्म देने वाले कुछ मूलभूत कारकों का पता लगाना अपरिहार्य हो जाता है यथा -

- सरकार द्वारा निरक्षरता उन्मूलन हेतु विभिन्न स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं परंतु लोगों में जागरूकता का अभाव होने के कारण संबद्ध अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम के तहत आंबटित संसाधनों का स्वहित के लिए उपयोग कर लिया जाता है और कार्यक्रमों की उपलब्धियाँ कागजों पर ही सिमट कर रह जाती हैं तथा वास्तविक कार्यक्रम अपने उद्देश्य में अंशतः ही सफल हो पाते हैं।
- अधिकांश कार्यक्रमों की कुछ व्यावहारिक कठिनाईयों के कारण भी परिणाम संतोषजनक नहीं प्राप्त हो पाता है जैसे स्वयंसेवी एजेंसियों में समन्वय का अभाव, कर्मचारियों के प्रशिक्षण में गुणवत्ता की कमी, सही मूल्यांकन का अभाव तथा पंचायती राज संस्थाओं का अविच्छिन्न रूप से सहायता का अभाव इत्यादि।
- अधिकांश प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक उपकरणों (चाक, श्यामपट्ट, दृश्य श्रव्य सामग्री) बच्चों को बैठने के लिए टाट पट्टी तथा संतोषजनक विद्यालय भवन के अभाव से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।
- कहीं कहीं एक ही शिक्षक को बिना किसी भवन के तथा किसी निजी स्थान पर कक्षा एक से पाँच तक के बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त विद्यालय के टूटे-फूटे भवन में प्रकाश की समुचित व्यवस्था भी नहीं होती।
- कुछ प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा बच्चों के साथ कठोर व्यवहार किया जाता है जिससे बच्चों में अध्ययन के दौरान नीरसता और भय उत्पन्न होने लगता है। फलतः वे बीच में ही पढ़ाई छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय प्राइवेट स्कूल उठाने लगते हैं जिसमें सदैव गुणवत्ता का अभाव होता है क्योंकि उसके शिक्षक अधिक पढ़े लिखे और प्रशिक्षित नहीं होते। साथ ही इन प्राइवेट स्कूलों में फ्रीस अधिक होने के कारण गरीब माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हो जाते हैं। फलतः निरक्षरता में वृद्धि होती है।
- छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के स्थान पर शिक्षा को ही व्यावसायिक कर दिया गया है और वार्षिक परीक्षा में प्रश्नों का ऐसा प्रारूप बनाया जाता है कि विद्यार्थी मात्र किसी तरह उत्तीर्ण होना ही अपना लक्ष्य समझने लगते हैं।
- प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम, उपयोगिता पर कम विचारधारा पर अधिक आधारित होते हैं। वह रूचिकर भी

नहीं होता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी आकर्षित नहीं हो पाते।

- इसके अतिरिक्त भी अन्य बहुत से कारण हैं जिनसे न केवल साक्षरता दर में अल्पवृद्धि हो रही है अपितु ग्रामीण शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। इसलिए अत्यन्त ही आवश्यक है कि मूलभूत कमियों को दूर किया जाए तथा ग्रामीण क्षेत्र को दृष्टि में रखते हुए गुणवतायुक्त और प्रभावशाली शिक्षा के स्तर को प्राप्त किया जाए।
- सबसे पहले निरक्षरता को एक सामाजिक समस्या माना जाए और इसके उन्मूलन के लिए स्थानीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए तथा समय समय पर परिचर्चाओं का आयोजन किया जाए जिसमें राष्ट्र स्तर की ख्याति प्राप्त विभूतियाँ भी सम्मिलित हों।
- चूँकि सरकार अकेले निरक्षरता की विशाल समस्या को दूर नहीं कर सकती इसलिए सरकार को चाहिए कि वह समुचित संसाधन उपलब्ध कराने के बाद ऐसी संस्थाओं, एजेंसियों और व्यक्तियों की पहचान करें जिसमें प्रत्यक्ष ज्ञान और वचनबद्धता हो। साथ ही निरीक्षण पर्यवेक्षण हेतु एक समिति भी बनानी चाहिए। इससे योजनाओं का समय समय पर मूल्यांकन भी होता रहेगा और वांछित परिणाम भी प्राप्त हो सकेगा।
- शिक्षकों की नियुक्ति पर पारदर्शिता का ध्यान रखा जाए तथा इन्हें वेतन व भत्ते समय समय पर दिए जाएँ जिससे उनमें असंतोष की भावना न उत्पन्न हो। साथ ही बेसिक शिक्षा परिषद्

जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा के संचालन का कार्य सौंपा गया है को अत्यधिक उत्तरदायित्वपूर्ण बनाया जाए।

- विद्यालयों का वातावरण सौहार्द्रपूर्ण और अध्यापक का छात्रों के प्रति व्यवहार प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए। साथ ही अध्यापकों द्वारा विद्यार्थी की अभिरूचि को देखकर उसको उपयुक्त विषय का चुनाव करने में परामर्श देना चाहिए।
- छात्रों की इच्छाओं का दमन न हो इसलिए उन्हें अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए तथा विद्यालय में खेलों के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वे शारीरिक व मानसिक विकारों से ग्रस्त न हों।
- दसवीं कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत विद्यार्थियों को व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। अतः इस हेतु ग्रामीण अंचलों में भी तकनीकी संस्थान स्थापित किए जाएँ जहाँ उन्हें उच्च कोटि की मूल्यपरक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त हो सके। साथ ही जिन ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या अधिक हो वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज अवश्य खोला जाए।
- प्रौढ़ साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जाए और इसे जन आंदोलन का रूप दिया जाए। महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों के छात्रों को अवकाश जो लगभग 120 दिनों का होता है के दिनों में ग्रामीण अंचल के प्रौढ़ों को शिक्षित करने के लिए प्रशस्ति पत्र देकर प्रोत्साहित भी किया जा सकता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि विकास का कोई भी मार्ग शिक्षा जैसे मूलभूत पैमाने से होकर ही गुज़रेगा। समतावादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। भूमंडलीकरण के इस युग में गाँवों के देश भारत के लिए अत्यंत ही आवश्यक है कि वह अपने ग्रामीण क्षेत्रों में निरक्षरता को दूर करके माध्यमिक स्तर से ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी युक्त गुणवत्तामूलक व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का दृढ़ संकल्प ले क्योंकि भारत की बौद्धिक संपदा को निकालकर राष्ट्रहित में उसका सर्वोत्तम उपयोग इसी क्षेत्र से संभव है। साथ ही देश के बुद्धिजीवी वर्ग, प्रशासनिक अधिकारी, मीडिया और स्वयंसेवी संस्था यदि ईमानदारी से स्वयं को ग्रामीण अंचल की ओर केंद्रित करें तो निश्चित ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे।

संदर्भ

- मासिक पत्रिका कुरूक्षेत्र, *ग्रामीण शिक्षा*, सितंबर 2012.
 _____, *ग्रामीण शिक्षा और निरंतर विकास*, सितंबर 2013.
 _____, *ग्रामीण शिक्षा*, सितंबर 2006, पृ.सं. 21 से 24.
<http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/educable/education-in-rural-india/>
<http://essaysandarticles.com/education-essays/rural-education/>
<http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000764/076492eo.pdf>
<http://www.censusindia.gov.in/>
http://www.data.gov.in/catalog/literacy-rate-india-nss-and-rgi#web_catalog_tabs_block_10
http://www.dataforall.org/dashboard/censusinfoindia_pca/
<http://www.educationforallinindia.com/page21.html>
<http://www.mapsofindia.com/my-india/education/india-needs-education-especially-rural-education>
http://www.theglobaljournals.com/ijar/file.php?val=March_2013_1362146819_53166_126.pdf